www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 यूपी में विद्यालय विलय नीति का विरोध करने...

3 कचहरी में फर्जी अधिवक्ता धरपकड़ अभियान, फर्जी...

4 धान की कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर के...

वर्ष: 9 | अंक: 262 | दिल्ली, बुधवार, 16 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

प्रशांत किशोर का दावा, बिहार में 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं बदलाव

बिहार (एजेन्सी)। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, जिसमें बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर के साथ-साथ एक नई व्यवस्था भी शामिल है... आरजेडी को यहाँ वोट इसलिए मिलते हैं क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, एआईएमआईएम हैदराबाद की पार्टी है। इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। बिहार में सिर्फ जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ही पार्टियाँ हैं। प्रशांत किशोर आगे कहा कि एक गठबंधन बीजेपी-जेडीयू का है और दूसरी तरफ आरजेडी का गठबंधन है। इसलिए बिहार के लोगों के पास सिर्फ तीन विकल्प हैं। पहला, अगर वे चाहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था जारी रहे, तो उन्हें नीतीश-बीजेपी को वोट देना चाहिए; दूसरा, अगर आप इस व्यवस्था से तंग आ चुके हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं—या तो आरजेडी का जंगल राज, अपराध और गुंडागर्दी वापस लाएँ, या एक ईमानदार और मजबूत प्रयास (जन सुराज) में शामिल हों।

भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, 5 मिनट बाद मिली जमानत

लखनऊ (एजेन्सी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि के एक मामले में लखनऊ की एक अदालत ने जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अध्यक्षता वाली एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो मुचलके भरने पर राहत दी। यह मानहानि का मामला गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत के समन का पालन करते हुए, गांधी लखनऊ में सांसदों और विधायकों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए।

शुभांशु शुक्ला के पिता से राजनाथ ने की बात

(एजेन्सी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला से बात की। शुभांशु 18 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी वापसी पर खुशी जताई और उनके पिता से कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि Welcome back to Earth! उन्होंने आगे लिखा कि ऐतिहासिक एक्सिओम मिशन 4 को सकुशल संपन्न कर सफल वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी व उनकी टीम को हार्दिक बधाई! आपकी उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी गौरवान्वित है। भारत आपके स्वागत को उत्सुक है। 15 जुलाई 2025 भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) यात्रा का समापन कर धरती पर लौट गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ड्रैगन यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। शुभांशु शुक्ला की कुशल वापसी पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में '2047 तक मिशन विकसित भारत में सीएसआर की भूमिका' पर आयोजित 12वें राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन में शिरकत की। (स्त्रोत: पीआईबी)

अगले 5 साल में युवाओं को मिलेगी 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार-नीतीश सरकार

(एजेन्सी)।

बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को 30 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिनमें अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने की योजना भी शामिल है। इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले घोषित इस फैसले को सत्तारूढ़ एनडीए सरकार द्वारा बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार सृजन पर कथित निष्क्रियता को लेकर विपक्ष की आलोचना का जवाब देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले रविवार को, मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में इसी तरह की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने यह भी दावा किया था कि 2005 से 2020 के बीच बिहार में आठ लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी गईं। कुमार ने पोस्ट में कहा, "अगले पाँच वर्षों (2025 से 2030) के लिए, हम एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियाँ और रोजगार के अवसर प्रदान करके इस लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निजी क्षेत्र, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में, नई नौकरियाँ और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएँगे।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में, सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगले पाँच वर्षों में, सात निश्चय के अंतर्गत युवा कौशल विकास के लिए चल रहे कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।" कुमार ने घोषणा की कि बिहार में कौशल विकास के लिए समर्पित एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसका नाम राज्य के प्रतिष्ठित नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करना है जो रोजगार के नए अवसर खोलें।

'यंगप्रेन्योर समिट 2025' में सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाया छात्र स्टार्टअप्स का हौंसला

इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत के विजन को बताया देश का भविष्य

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉन्फेडरेशन ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 'यंगप्रेन्योर समिट 2025' में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समिट का उद्देश्य था-स्कूली छात्रों द्वारा शुरू किए गए इनोवेटिव स्टार्टअप्स को मंच देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना रहा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्ट अप में नई कामयाबी प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। बच्चों के स्टार्टअप्स में दिखी नवोन्मेषी सोच, प्रतिबद्धता और जज्बे को सराहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की पीढ़ी न केवल स्मार्ट है, बल्कि बेहद विजनरी भी है-उन्हें पता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है और क्या बनना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सोच और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। उनके इनोवेटिव आइडिया ही आज देश में नए स्टार्टअप्स की नींव बन रहे हैं। इतने कम उम्र में छात्रों द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं और वे निश्चित ही भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने समिट की थीम 'Made in Mind, Built in Bharat' की सराहना करते हुए इसे देश की नवाचार संस्कृति की सही अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि आज का भारत, जो कभी दुनिया की नजरों में पिछड़ा समझा जाता था, आज गर्व, संस्कृति और तकनीकी शक्ति का प्रतीक बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में जब देश के स्टूडेंट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं, तो ऐसे आयोजनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का हर युवा, जब यह सोचकर आगे बढ़ेगा कि 'सबसे पहले मेरा देश', तभी भारत आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में भाग लेना उनके लिए बेहद यादगार रहा और छात्र-छात्राओं से मिले स्नेह और जोश को वह जीवन भर संजोकर रखेंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मोतिहारी आगमन ऐतिहासिक होगा: मनीष कुमार शेखर

पशुधन विभाग, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मनीष शेखर ने 18 जुलाई को मोतिहारी गांधी मैदान में भारी संख्या में पहुंचने की किया अपील

संजना भारती संवाददाता

मोतिहारी। पशुधन विभाग, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक श्री मनीष कुमार शेखर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को मोतिहारी आगमन पर गांधी मैदान में भारी संख्या में चम्पारण वासियों को पहुंचने की अपील किया है। शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के जन जन के नेता हैं जिनका चम्पारण वासियों पर विशेष स्नेह रहता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी जो विकसित बिहार की नींव के रूप में होगा। शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास के संकल्प से लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत तेजी से विकास कर रहा है जो दुनिया के केन्द्र में बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी वर्गों के लोगों के जननेता

है जो सबका समान रूप से ख्याल रखते हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोतिहारी आगमन से चम्पारण के विकास में नया अध्याय जुड़ने वाला है।

संसद के मानसून सत्र में आठ नए बिल ला सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेन्सी)। मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में आठ नए बिल ला सकती है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित संभावित कार्यों में शामिल हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने की मंशा को शामिल करने से यह संकेत मिलता है कि सरकार की पूर्वोत्तर राज्य में 13 फरवरी को लागू किए गए उपाय को तत्काल वापस लेने की कोई योजना नहीं है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए हर छह महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है और वर्तमान समय सीमा 13 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसके अलावा, 2025-26 के लिए अनुदान मांगों (मणिपुर) से संबंधित विनियोग विधेयक संसद के समक्ष लाया जाएगा। सरकार आयकर विधेयक, 2025 भी लाने की योजना बना रही है, इस उम्मीद के साथ कि प्रवर समिति मानसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह विधेयक 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था और जांच के लिए प्रवर समिति को भेजा गया था। अस्थायी सूची में असैन्य परमाणु दायित्व व्यवस्था में बदलाव संबंधी बहुप्रतीक्षित विधेयकों का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, सरकार सत्र के दौरान एक विधेयक ला सकती है, भले ही वह अस्थायी सूची में न हो। नए विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को भी इस सत्र में पारित किया जाना प्रस्तावित है, जो 21 अगस्त को समाप्त होगा।

मंत्री ने जीटीबी अस्पताल में हो रहे सिविक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों की समीक्षा की

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने जीटीबी अस्पताल में चल रहे सभी तरह के सिविक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की।

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के बाद कहा कि 'स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली' के संकल्प को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहद मजबूत बनाने में जुटी है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में चल रहे सभी सिविक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सिंह ने जीटीबी अस्पताल में 14 नए आईसीयू बेड्स को तुरंत चालू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आईसीयू जैसी जरूरी मेडिकल सुविधाएं जल्द से जल्द मरीजों की सेवा में समर्पित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सभी कमियों को

तुरंत दूर करने के निर्देश देते हुए कहा कि जीटीबी अस्पताल की पुरानी और खराब पड़ी लिफ्ट को तत्काल बदलकर तुरंत चालू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के साथ ही डॉक्टर और स्टाफ को भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मंत्री ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि इमरजेंसी वार्ड को जल्द से जल्द वेंटिलेटर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से अपग्रेड किया जाए।

अस्पताल आने वाले मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि अस्पताल के कैंपस में खुले पड़े सभी बिजली के तारों को तुरंत उचित तरीके से कवर किया जाए। ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो।

दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के सीमावर्ती इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग रोजाना इलाज करवाने पहुंचते हैं। जिसके कारण अस्पताल में मरीजों की अत्यधिक भीड़ लगी रहती है। मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंत्री ने अस्पताल में भीड़ के प्रबंधन की प्रभावी योजना लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मरीजों की आवाजाही और अतिरिक्त सहायता डेस्क जैसी व्यवस्थाएं को सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे अस्पताल पहुंचे मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने चिकित्सा अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में चल रहे सभी सिविक और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की प्रगति का खुद निरीक्षण करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपें।

राजकीय मेडीकल कॉलेज में खुला देश का 75वां व प्रदेश का 6वां प्रधानमंत्री दिव्यांशा केन्द्र

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश के 75वें व प्रदेश के 6वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केन्द्र का उद्घाटन मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ में केंद्रीय राज्य मंत्री बी0एल0 वर्मा द्वारा फीता काटकर व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रजवलन कर किया गया। उन्होंने कहा कि बदायूं में इस केन्द्र की स्थापना से क्षेत्र के दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को अब स्थानीय स्तर पर ही सहायक उपकरणों की सुविधा सहायता प्राप्त होगी।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री बी0एल0 वर्मा ने कहा कि प्रदेश में जनपद गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, नोएडा व चित्रकूट में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र संचालित हैं। मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में देश का 75वां व प्रदेश का 6वां प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र खोला गया है, इसका सीधा लाभ दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पहले दिव्यांगजनों को सात प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र मिलते थे लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास से अब इसको बढ़कर 21 कर दिया गया है और अब दिव्यांगजनों को 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आरक्षण को 03 प्रतिशत

से बढ़ाकर 05 प्रतिशत किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विकलांगजनों को दिव्यांगजन नाम दिया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों ने देश का मान बढ़ाया है। पैरा ओलंपिक में ओलंपिक से ज्यादा मैडल जीतकर दिव्यांगजनों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री दिव्यांशा केन्द्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को एक ही स्थान पर सहायक उपकरणों की जांच, मूल्यांकन, परामर्श, वितरण एवं अनुवर्ती सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना है। इन केन्द्रों की स्थापना मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से की जा रही है।

उन्होंने बताया कि यह केन्द्र विशेष रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सरकार की एडिप योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, वैसाखी, श्रवण यंत्र, दृष्टि बाधित हेतु सुगम्य केन, छड़ी, वॉकर, कमोड चेयर, नी-ब्रेस, बेल्ट, केलिपर्स, श्रवण मूल्यांकन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह केन्द्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देशभर में 74 प्रधानमंत्री दिव्यांशा केन्द्र संचालित हैं और इस 75वें केन्द्र की स्थापना के साथ यह संख्या एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुकी है। अब तक 1.40 लाख से अधिक लाभार्थियों को 179.15 लाख रुपये मूल्य के सहायक उपकरणों का वितरण किया जा चुका है।

उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए।

मुंबई में मूसलाधार बारिश, निचले इलाके जलमग्न

(एजेन्सी)।

मुंबई। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों जैसे बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव और पूर्वी उपनगरों जैसे मुलुंड, विक्रोली में पिछले आधे घंटे से भारी बारिश जारी है। शहर में जलभराव के कारण अंधेरी सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अंधेरी, विलेपार्ले, सांताक्रूज, खार और बांद्रा जैसे क्षेत्रों में पानी भर गया है, जबकि बीकेसी, कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर और भांडुप में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। यहां भी निचले इलाकों में जलभराव होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

इन घटनाक्रमों के बीच, मुंबई पुलिस ने निवासियों को तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2 फीट पानी जमा होने के कारण, अंधेरी पश्चिम, मुंबई में अंधेरी सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और गोखले ब्रिज के रास्ते डायवर्ट किया गया है।

ठाणे और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अपने नियमित बुलेटिन में, आईएमडी ने कहा कि अगले चार दिनों में मुंबई और आसपास के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

सन्त-महात्माओं की धरती है भारत: डॉ. अरविंद शर्मा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के सहकारिता, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत सन्त-महापुरुषों को धरती है, जो निरन्तर धर्म ध्वजा मजबूती के साथ पकड़ कर समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वो युवाओं की धर्म ज्ञान में भागीदारी बढ़ाएं, ताकि वो प्रतिस्पर्धा भरे इस दौर में अपने दायित्व को मजबूती से निभाएं। मंगलवार को डॉ. अरविंद शर्मा पंचकूला में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गुरु मां सोनाक्षी नंद गिरी जी महाराज के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि भारतवर्ष संतों की और ऋषियों की भूमि है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने

सभी धर्म प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत का मूल आधार ही आध्यात्मिक है। डॉ. अरविंद शर्मा ने इस अवसर पर महामंडलेश्वर गुरु मां सोनाक्षी नंदगिरी जी महाराज से देश और प्रदेश की उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी, पंचकूला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया सहित विभिन्न गणमान्य लोग और काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

समोसे-जलेबी पर सरकारी फरमान

सिगरेट और शराब को लेकर वैधानिक चेतावनी दी जाती है कि इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मोदी सरकार समोसे और जलेबी पर भी ऐसी ही चेतावनी जारी करने का फरमान निकाल चुकी है। जल्द ही देश के सभी सरकारी संस्थानों में जल्द ही ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे जो साफ बताएंगे कि आपकी प्लेट में आया समोसे और जलेबी का स्वाद असल में कितना चीनी और तेल लेकर आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी संस्थानों को कहा है कि कैफेटेरिया और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे बोर्ड लगाए जाएं, जो सबसे प्रचलित भारतीय नाश्ते में छिपी चीनी और तेल की मात्रा दिखाएं। इनका मकसद लोगों को यह बताना है कि वे जो कुछ भी खा रहे हैं वह स्वाद में भले लाजवाब हो, लेकिन सेहत के लिए कितना भारी पड़ सकता है। एम्स नागपुर के अधिकारियों ने इसे फूड लेबलिंग में एक नया मोड़ कहा है, कि 'अब खाने के साथ भी उतनी ही गंभीर चेतावनी दिखेगी, जैसी सिगरेट पर होती है।' पाठकों को बता दें कि तले हुए और मीठे खाद्य पदार्थों के लिए ऐसी चेतावनी जारी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समोसा, जलेबी, पकौड़े, वड़ा पाव, गुलाब जामुन, लड्डू, खस्ता कचौरी, मिठाइयों की थालियां इन सबके सेवन पर कितनी शक्कर और तेल आपके शरीर में जाएगा, इस बारे में बाकायदा बोर्ड पर सूचना लगी होगी। इस पूरी मुहिम को देश की स्वास्थ्य समस्या के निदान के तौर पर पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरह भारत में मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है। देश में हर पांचवां शहरी वयस्क बढ़े वजन का शिकार है। 2050 तक देश में लगभग 45 करोड़ लोग मोटापे से ग्रसित होंगे, ऐसी आशंका है। बच्चों में भी मोटापा और डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल, ट्रांस फैट और चीनी से भरे खाद्य पदार्थों के खाने का चलन बढ़ा है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा के अध्यक्ष अमर अमले ने कहा है कि यह फूड लेबलिंग की शुरूआत है जो सिगरेट की चेतावनियों जितनी गंभीर होती जा रही है। चीनी और ट्रांस फैट नए तंबाकू हैं. लोगों को यह जानने का हक है कि वे क्या खा रहे हैं। वैसे मोटापे पर यह चिंता मोदीजी की मुहिम से ही निकली हुई दिख रही है। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मोटापे की गंभीर समस्या का जिक्र करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला दिया था कि 2022 में दुनिया भर में 250 करोड़ लोग जरूरत से ज्यादा वजन के शिकार थे। इसके बाद मोदीजी ने खाने में कम तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी और मोटापे के खिलाफ लड़ाई में आनंद महिंद्रा (उद्योगपति), निरहुआ हिंदुस्तानी (अभिनेता), मनु भाकर (ओलंपिक पदक विजेता), साइखोम मीराबाई चानू (भारोत्तोलक), मोहनलाल (अभिनेता), नंदन नीलेकणी (इन्फोसिस के सह-संस्थापक), आर. माधवन (अभिनेता), श्रेया घोषाल (गायिका), सुधा मूर्ति (राज्यसभा सांसद) और ओमर अब्दुल्ला (मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर) को नामित किया था कि वे आगे इसी तरह 10 और लोगों को नामित करें और मोटापे के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी ने इसे व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी बताया था। उन्होंने मोटापा खत्म करने के लिए तेल की खपत कम करने की अपील की थी। भारत जैसे देश में, जहां कुपोषण एक गंभीर समस्या है, पहले नरेन्द्र मोदी और अब मोदी सरकार का यह अभियान फ्रांस की रानी की सलाह की तरह लगता है कि गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वे केक खा लें। वैसे नरेन्द्र मोदी चाहें तो इस अभियान को अपनी उपलब्धि के तौर पर भी पेश कर सकते हैं कि 2014 में उन्होंने ऐलान किया था कि 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करेंगे और अब कुपोषण नहीं मोटापे से मुक्ति की लड़ाई छिड़ गई है। वैसे सरकार को आईना दिखाने के लिए यह तथ्य काफी है कि देश में अगर मोटापा शहरों और संपन्न तबकों में बढ़ा है, तो उसके साथ कुपोषण की समस्या और गंभीर हुई है। पिछले साल ही मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि देश में 5 साल से कम उम्र के करीब 60 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 साल तक की उम्र के 36 प्रतिशत बच्चे बौने हैं, 17 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं और 6 प्रतिशत बच्चे दुबलेपन का शिकार हैं।

जयंती

अरुणा आसफ अली

जन्म-16 जुलाई, 1909; मृत्यु-29 जुलाई, 1996) का नाम भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किये थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी, जुझारू नेता श्रीमती अरुणा आसफ अली का नाम इतिहास में दर्ज है। अरुणा आसफ अली ने सन 1942 ई. के 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। देश को आजाद कराने के लिए अरुणा जी निरंतर वर्षों अंग्रेजों से संघर्ष करती रही थीं।

पुण्यतिथि

सुरेखा सीकरी

जन्म-19 अप्रॅल, 1945, नई दिल्ली; मृत्यु-16 जुलाई, 2021, मुम्बई) एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार थीं। वह मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय थीं। वर्ष 2018 में आयी बॉलीवुड फिल्म 'बधाई हो' और धारावाहिक टेलीविजन शो 'बालिका बधु' (2008) के लिए सुरेखा सीकरी को जाना जाता है। धारावाहिक 'बालिका वधु' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। वह हिंदी रंगमंच में वर्ष 1978 से लेकर 2021 तक सक्रिय थीं। सुरेखा सीकरी ने अपने कॅरियर की शुरूआत वर्ष 1978 में राजनीतिक ड्रामा फिल्म 'कि स्सा कुर्सी का है' से की थी।

कल मिलेंगे

एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला-10 रुपये दो, तब बताऊंगा...
पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा-अब बताओ!
बच्चा-मैं तो 10 रुपये के लिए रो रहा था.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

यूपी में विद्यालय विलय नीति का विरोध करने वाले बच्चों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं

स्कूलों की मर्जर पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के बीच जो भ्रम और विरोध की स्थिति देखी जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इस नीति के उद्देश्यों से भलीभांति अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए विशेषकर वे शिक्षक, जिनका स्थानांतरण (ट्रांसफर) दूर-दराज क्षेत्रों में होने की आशंका है, इस नीति को अपने भविष्य के लिए खतरा मानकर विरोध कर रहे हैं

-नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज (विलय) करने का फैसला किया तो इस पर राजनीति और हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी नेता इस नीति को छात्रों के विरोध में बताते हुए बयानबाजी करने लगे, शिक्षकों की ओर से भी इस नीति का विरोध जताया जाने लगा, अभिभावक भी चिंतित होने लगे, कोई इस नीति के विरोध में कोर्ट चला गया तो कोई सोशल मीडिया पर इसके विरोध में तमाम पोस्टें किये जा रहा है। लेकिन आप इस नीति का विरोध कर रहे लोगों की बातों को सुनेंगे या उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ेंगे तो एक बात साफ हो जायेगी कि इन्हें शिक्षा में सुधार से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को अपनी राजनीति चमकानी है तो किसी को अपने लिये बरसों से बने सुविधाजनक माहौल से बाहर नहीं निकलना है।

जबकि असल में देखा जाये तो योगी सरकार की स्कूलों को मर्ज करने की नीति केवल प्रशासनिक सुधार भर नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और विद्यार्थियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से एक दूरदर्शी कदम है। इस नीति के दूरगामी प्रभाव छात्रों और उनके अभिभावकों के हित में साबित होंगे। हम आपको बता दें कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को पास के ज्यादा छात्रों वाले विद्यालयों में समायोजित कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज किया जाना इस नीति की वैधता का प्रमाण भी है।

स्कूलों को मर्ज करने की नीति का विरोध करने वालों को समझना चाहिए कि छोटे-छोटे विद्यालयों में अक्सर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिलती है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी चीजों का भी अभाव होता है। जब दो या तीन स्कूलों को मर्ज कर एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा, तो संसाधनों का केन्द्रीयकरण होगा। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल, अच्छी बिल्डिंग, खेल-कूद और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इसके अलावा, अभी कई स्कूलों में एक या दो अध्यापक ही पूरे विद्यालय का भार उठा रहे हैं। इससे न तो शिक्षक विषय विशेषज्ञ बन पाते हैं और न ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। मर्ज किए गए बड़े स्कूलों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार के लिए आसान होगा। इससे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में भी बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। साथ ही मर्जिंग के बाद स्कूलों में केवल छात्र संख्या ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि प्रतियोगिता, नवाचार और गतिविधियों के अवसर भी बढ़ेंगे। बड़े स्कूलों में सामान्यतः बेहतर शैक्षणिक माहौल होता है, जिससे बच्चों के सीखने का स्तर स्वतः ही ऊपर उठता है। इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी और आगे चलकर वे प्रतियोगी परीक्षाओं व कॅरियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने को मजबूर होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा स्तर कमजोर होता है। लेकिन जब सरकारी स्कूल ही बेहतर आधारभूत सुविधाओं और योग्य शिक्षकों से सुसज्जित होंगे, तो अभिभावकों का भरोसा इन स्कूलों पर बढ़ेगा। इससे शिक्षा पर उनका अतिरिक्त आर्थिक भार भी घटेगा।

इसके अलावा, कम स्कूलों का प्रबंधन करना सरकार और शिक्षा विभाग दोनों के लिए आसान होगा। निरीक्षण, ऑडिट और सुधारात्मक कदम जल्दी और प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे। इससे विद्यालयों में जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार या लापरवाही पर भी अंकुश लगेगा।

वहीं स्कूलों की मर्जर पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के बीच जो भ्रम और विरोध की स्थिति देखी जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इस नीति के उद्देश्यों से भलीभांति अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए विशेषकर वे शिक्षक, जिनका स्थानांतरण (ट्रांसफर) दूर-दराज क्षेत्रों में होने की आशंका है, इस नीति को अपने भविष्य के लिए खतरा मानकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि वे इस नीति के दीर्घकालिक लाभों और शिक्षा व्यवस्था में इसके सकारात्मक प्रभाव को समझेंगे तो वह स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह परिवर्तन उनके लिए नुकसान नहीं, बल्कि अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है।

बहुत से शिक्षक सोच रहे हैं कि स्कूलों के मर्जर से उनके वर्तमान स्कूल बंद हो जाएंगे और उन्हें दूर के विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वह यह मानते हैं कि इससे उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले शिक्षकों को अपना विरोध छोड़ देना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आज जिन छोटे स्कूलों में वह काम कर रहे हैं, वहाँ न तो पर्याप्त छात्र हैं और न ही आधारभूत सुविधाएँ। स्कूलों के मर्जर के बाद बड़े, बेहतर संसाधनयुक्त विद्यालयों में तैनाती मिलने से काम करने का वातावरण सुधरेगा। साफ-सुथरी बिल्डिंग, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और डिजिटल क्लास जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, जहाँ बच्चे अधिक होंगे, वहाँ शिक्षकों की जिम्मेदारी के साथ-साथ उनके अनुभव और दक्षता में भी वृद्धि होगी। ऐसे विद्यालयों में कार्य करते हुए शिक्षक नवाचार, प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग जैसी योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे। इससे उनके कॅरियर में प्रगति के द्वार खुलेंगे। शिक्षकों को यह भी समझना चाहिए कि स्थानांतरण कोई दंड नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के संतुलन का माध्यम है। जिन शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा, उन्हें भी बेहतर सुविधा वाले विद्यालयों में ही भेजा जाएगा। लंबे समय में यह व्यवस्था स्थिर होगी और अराजकता कम होगी।

देखा जाये तो एक शिक्षक का प्रथम कर्तव्य बच्चों के भविष्य को संवारना है। स्कूल मर्जर से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, उनका ड्रॉपआउट रेट घटेगा और वे प्रतिस्पर्धी भविष्य के लिए तैयार होंगे। जब शिक्षा बेहतर होगी, तो शिक्षक का सम्मान भी स्वतः बढ़ेगा। इसके अलावा, छोटे-छोटे विद्यालयों में बिखरी शिक्षक शक्ति को एक जगह लाकर सामूहिक रूप से मजबूत किया जाएगा। इससे शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा और शिक्षकों की भूमिका ज्यादा प्रभावशाली बनेगी।

देखा जाये तो विद्यालय विलय नीति से डरने या उसका विरोध करने का कोई तर्क नहीं है। बदलाव के हर कदम में प्रारंभिक कठिनाई होती है, लेकिन दूरदर्शिता रखने वाले शिक्षक समझते हैं कि यह नीति बच्चों के भविष्य, शिक्षकों की गरिमा और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे डर या भ्रम छोड़कर इस नीति का स्वागत करें और इसे अपने सुनहरे भविष्य के अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक सोच के साथ परिवर्तन को अपनाना ही चाहिए क्योंकि यही भविष्य का आधार होता है। अब जरा बात उन अभिभावकों की कर ली जाये जो अपने बच्चे के स्कूल के दूर हो जाने की चिंता से ग्रस्त हैं। देखा जाये तो अभिभावकों के मन में यह चिंता उठना स्वाभाविक ही है कि अब उनके बच्चे का स्कूल पहले से कुछ दूर हो जाएगा। ऐसे अभिभावक सोच रहे हैं कि बच्चों को रोजाना ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे परेशानी बढ़ेगी। लेकिन वक्त की आवश्यकता यह है कि अभिभावकों को दूरी की चिंता छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल आज के समय में यह देखना अधिक जरूरी है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ उसे कैसी शिक्षा, कैसी सुविधाएं और कैसे अवसर मिल रहे हैं। यदि स्कूल थोड़ा दूर है लेकिन वहाँ अच्छे शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, डिजिटल शिक्षा, खेलकूद और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के अवसर मिल रहे हैं तो यह दूरी बच्चों के भविष्य के सामने बिल्कुल छोटी बात है।

इसके अलावा, निकट का स्कूल अगर सुविधाविहीन, अध्यापकविहीन और कमजोर है, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक विकास बाधित होगा। जबकि कुछ किलोमीटर दूर का स्कूल अगर बच्चों को आधुनिक शिक्षा, अनुशासन और अवसर दे रहा है, तो वही बच्चा आगे चलकर आत्मनिर्भर और सफल बन पाएगा।

देखा जाये तो हर गाँव में छोटा-छोटा स्कूल खोल देने से शिक्षा मजबूत नहीं होती। एक ऐसा स्कूल जहाँ योग्य शिक्षक, बेहतर पढ़ाई, खेल का मैदान, आधुनिक लैब और स्मार्ट क्लास हो, बच्चों के विकास के लिए ज्यादा जरूरी है। वहाँ बच्चे प्रतिस्पर्धा सीखेंगे, दोस्त बनाएंगे और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ेंगे। अभिभावकों को यह पता होना चाहिए कि ऐसी तमाम देशी-विदेशी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि भारत में बच्चों की शिक्षण गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को समझना होगा कि स्कूल की दूरी बढ़ना असली चुनौती नहीं है, असली चुनौती है अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलना।

अभिभावकों को समझना होगा कि आज भले ही बच्चा स्कूल जाने के लिए 2-3 किलोमीटर ज्यादा चले, लेकिन जब वह अच्छे स्कूल में पढ़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा, तो उसी माता-पिता को गर्व होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए यह छोटा सा समझौता किया। अभिभावकों को समझना होगा कि आपका फर्ज सिर्फ यह नहीं कि बच्चा घर के नजदीक स्कूल में पढ़े। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसे ऐसा माहौल दें, जहाँ वह अच्छे शिक्षक, संसाधन और अवसर पाकर अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसलिए स्कूल पास हो या दूर, अगर वहाँ पढ़ाई बेहतर है, तो वही सही विकल्प है।

दूरी की नहीं, गुणवत्ता की चिंता करें। भविष्य तभी बदलेगा, जब शिक्षा मजबूत होगी। सबको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के विलय से शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। बच्चों को वह सब मिलेगा, जो अभी बड़े शहरों के स्कूलों में मिलता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को प्राथमिकता दें, न कि केवल दूरी को। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा का हर कदम भविष्य तक जाता है-चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों न हो।" बहरहाल, देखा जाये तो विद्यालयों के विलय की यह नीति केवल ढांचागत सुधार नहीं है, बल्कि शिक्षा के स्तर को सुधारने, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने और अभिभावकों के आर्थिक-सामाजिक हितों की रक्षा करने की दूरगामी सोच का हिस्सा है। यदि इसे पारदर्शिता से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत, प्रभावी और लोकप्रिय विकल्प बन सकते हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

अब मतदाता सूचियों में विदेशी नामों का हौवा

कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक जन-धारणा बनाने का और उसका अधिकतम प्रचार करने का ही खेल है। इस खेल में इस तरह का 'सूत्रों' के नाम पर किया जाने वाला प्रचार, खासतौर पर मददगार होता है, जिसे विश्वसनीय बनाने के लिए जिस संस्था के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, उस संस्था को मंडन या खंडन में से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होती है और इस तरह वास्तव में वह मौन स्वीकृति से इस धारणा के बनने में मदद ही कर रही होती है

-राजेंद्र शर्मा

जिसकी आशंका थी, बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के पीछे के असली खेल का पर्दे के पीछे से झांकना शुरू हो गया है। यह शुरूआत हुई है इसके दावों के साथ कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के क्रम में घर-घर जाने से मिल रही जानकारियों से पता चला है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नेपाली, बंगलादेशी और म्यांमार के लोगों के नाम हैं। बेशक, अभी तक ये कथित जानकारियां, चुनाव आयोग में मौजूद 'सूत्रों' से आ रही जानकारियों के तौर पर ही मीडिया में आयी हैं। चुनाव आयोग ने खुद औपचारिक रूप से न तो ऐसा कोई बयान दिया है और न ऐसा कोई दावा किया है। बहरहाल, ये खबरें जितने बड़े पैमाने पर और वास्तव में जिस तरह हर जगह ही मीडिया में आयी हैं, उससे साफ है कि यह दबी-छुपी जानकारी का मामला नहीं है, जिसे किन्हीं इक्का-दुक्का सूत्रों ने उजागर कर दिया हो और इस या उस मीडिया संस्थान के हाथ लग गयी हों। इसके विपरीत, यह 'सूत्रों' के नाम पर खुद चुनाव आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर खबर प्लांट किए जाने का मामला है। यह किसी से छुपा नहीं है कि मोदी राज की अपारदर्शिता की आम कार्य संस्कृति में रच-बसकर चुनाव आयोग ने भी अपनी स्वतंत्र भूमिका के अधिकतम पारदर्शिता के तकाजों को भुलाकर, मीडिया के जरिए जनता से और स्वयं सीधे राजनीतिक पार्टियों के साथ भी संवाद कम से कम कर दिया है। मोदी राज की तरह अब चुनाव आयोग भी संवाददाता सम्मेलन और चुनाव प्रक्रिया की मुख्य हितधारक, राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकें कम से कम करता है और ज्यादा से ज्यादा 'सूत्रों' के नाम पर खबरें प्लांट करने का सहारा लेता है। यही बड़ी संख्या में विदेशियों के नाम मतदाता सूचियों में होने के प्रचार के मामले में हो रहा है।

कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक जन-धारणा बनाने का और उसका अधिकतम प्रचार करने का ही खेल है। इस खेल में इस तरह का 'सूत्रों' के नाम पर किया जाने वाला प्रचार, खासतौर पर मददगार होता है, जिसे विश्वसनीय बनाने के लिए जिस संस्था के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, उस संस्था को मंडन या खंडन में से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होती है और इस तरह वास्तव में वह मौन स्वीकृति से इस धारणा के बनने में मदद ही कर रही होती है। यह मदद महत्वपूर्ण रूप से इस अर्थ में भी की जा रही होती है कि इस खबर, जिसे वास्तव में अफवाह ही कहना चाहिए, की जांच के लिए सवालों के जवाब देने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 'मतदाता सूची में बड़ी संख्या में विदेशियों के नाम' होने की इस धारणा के सिलसिले में, जिसको सत्ताधारी संघ-भाजपा से जुड़ा पूरा का पूरा प्रचार सिस्टम जोर-शोर से फैलाने में लगा हुआ है, न तो इसका कहीं कोई जवाब मिलेगा कि ये 'बड़ी संख्या' आखिरकार है कितनी और न ही इसका कोई जवाब मिलेगा कि घर-घर जाने के क्रम में अधिकारियों को यह जानकारी मिली कैसे? कथित रूप से घर-घर गए, निचले दर्जे के अधिकारियों ने, जिनमें ज्यादातर बीएलओ की भूमिका अदा कर रहे स्कूल अध्यापक ही हैं, कैसे जाना, किस तरह की जांच के जरिए जाना कि मतदाता सूची में शामिल अनेक नाम, वास्तव में विदेशियों के हैं?

दूसरी ओर, 'सूत्रों' के नाम पर फैलायी जा रही इन अफवाहों में आयोग के नाम पर ही यह अफवाह और जोड़ दी गयी है कि इन नामों को पक्की मतदाता सूची में से हटा दिया जाएगा। कैसे? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है, हालांकि गोल-मोल तरीके से यह जरूर कहा जा रहा है कि 'जांच के बाद' नामों को हटा दिया जाएगा। लेकिन, जैसा कि बिहार में जारी पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी कानूनी चुनौतियों में बलपूर्वक रेखांकित किया गया है और अदालत भी जिससे सहमत नजर आयी है, नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग के दायरे में आता ही नहीं है। ऐसे में आयोग किसी भी रूप में नागरिकता की जांच को, मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने / हटाने का आधार बना ही नहीं सकता है। लेकिन, उद्देश्य उतना नाम हटाना नहीं है, जितना विदेशी घुसपैठ का हौवा खड़ा करना है।

इस खेल के दो मकसद तो आसानी से पहचाने भी जा सकते हैं। पहला तो यही कि जिस बात की शुरू से ही आशंका जतायी जा रही थी कि, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की इस पूरी प्रक्रिया का ही मकसद मतदाता सूचियों की साफ-सफाई के नाम पर, इन सूचियों से वैध मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या को बाहर करना है, उसका इस तरह से औचित्य सिद्ध किया जा रहा होगा। और चूंकि इस पुनरीक्षण की पद्धति को इस तरह से ढाला गया कि यह ग्रामीण व शहरी गरीबों पर, कमजोर तबकों/जाति के लोगों पर, कम पढ़े-लिखे लोगों पर, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा चोट करेगी, जबकि संपन्न, शिक्षित, सवर्ण पर सबसे कम चोट करेगी, मतदाता सूचियों की यह 'सफाई', वस्तुगत रूप से सत्तापक्ष की मदद करेगी, जिसे वंचितों का अपेक्षाकृत कम और अधिकार-संपन्नों का अपेक्षाकृत अधिक समर्थन हासिल है। चुनाव आयोग की इस सब में इसलिए भी अतिरिक्त दिलचस्पी हो सकती है कि इस प्रक्रिया के अंत में उल्लेखनीय संख्या में मतदाताओं की छंटनी को, जो इस प्रक्रिया में ही निहित है, 'विदेशियों' की छंटनी के नाम पर न सिर्फ उचित ठहराया जा रहा होगा बल्कि आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण की अपनी पद्धति की खामियों का जवाब देने के बजाय, इतने नामों का छांटा जाना जिसका साक्ष्य है, कथित रूप से विदेशियों से देश की जनतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए अपनी पीठ भी ठोक सकेगा। याद रहे कि मतदाता सूची में विदेशी नामों की 'खबरों' ने खासतौर पर तब जोर पकड़ा है, जब मुख्यधारा के मीडिया के सरकार की ही तरह चुनाव आयोग का भी भोंपू बनने के बावजूद, कई साहसी स्वतंत्र पत्रकारों ने किसी भी तरह तय समय सीमा में इस नामुमकिन पुनरीक्षण को मुमकिन कर दिखाने की हड़बड़ी में, चुनाव आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर अपने ही बनाए तमाम नियम कायदों को उठाकर ताक पर ही रख देने की सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह मतदाता सूचियों में भारी धांधली और मनमानी की स्थितियां बनाता है। इस तरह ध्यान बंटाने के हथकंडों के जरिए सवालों से बचना तो, वर्तमान शासकीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा ही बन चुका है।

दूसरे की जमीन का प्यासा चीन? समंदर पर भी जताता है हक

(एजेन्सी)।

क्या मानचित्र पर नाम मायने रखते हैं? जब वे सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हो तो जवाब हां में ही मिलता है। चीन एक ऐसा देश है जिसका दुनिया में कोई देश ऐतबार नहीं कर सकता है। दुनियाभर में भी कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। चीन ताइवान पर जबरन कब्जे की फिराक में दशकों से बैठा है। नेपाल से दोस्ती की आड़ में उसके इलाके पर टेढ़ी नजर है। हांगकांग की आजादी का अतिक्रमण हो या साउथ चाइना सी में वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया से टकराव। सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान से लड़ रहा। मंगोलिया में कोयला भंडार पर चीन की नजर। भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का चीनी नाम रखने के बाद चीन की हिमाकत बढती ही जा रही है। चीन एक शातिर देश है। निश्चित ही तिब्बत पर कब्जा करने की मंशा भारत को ही केंद्रित करके की गई होगी। तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात एक तो भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे सदाबहार मित्र का पड़ोसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के माध्यम से बना। अर्थात पीओके से ही चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में चीन की नीति से संपूर्ण विश्व परिचित है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दक्षिण चीन सागर पर वो अपने एकाधिकार का दावा करता है। लेकिन दक्षिण चीन सागर किसी एक देश की धरोहर न होकर एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक मार्ग है। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देश पर प्राकृतिक तेल, गैस, ऊर्जा, मस्थ सुरक्षा इत्यादि हेतु निर्भर हैं। ऐसे में चीन द्वारा विवादित द्वीपों पर कब्जा और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के माध्यम से अपने क्षेत्र में वृद्धि करने की नीति और कृत्रिम द्वीपों पर नौसैनिक अड्डा बनाए जाने के कारण दक्षिण चीन सागर के तटीय देश वियतमान, फिलिपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि चीन से नाराज हैं। इसलिए ये तटवर्ती देश चीन से दूरी बना रहे हैं और भारत के साथ नजदीक आ रहे हैं। चीन की विस्तारवादी मानसिकता के कारण तटवर्ती देश चीन के विरूद्ध लामबंद हो रहे हैं। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर में चीनी वर्चस्व चीन को न केवल महाशक्तियों से अपितु उसके पड़ोसियों से भी दूर कर रहा है। भारत तिब्बत और भूटान की सीमा पर देखें तो चीन भूटान के भूभाग को हड़पने की नीयत के कारण सीमा पर तनाव जारी है। दरअसल, तिब्बत की तरह भूटान को छोटा और कमजोर राष्ट्र समझकर चीन की मंशा उचित प्रतीत नहीं होती। डोकलाम के संदर्भ में विवादस्पद नक्शे को जारी कर चीन ने उस भूभाग को अपना बताकर मंशा जाहिर कर दी। भूटान सरकार का भारत सरकार के साथ सुरक्षा समझौता है। ऐसे में भूटान की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार के पास है। तिब्बत की दुर्दशा देखकर भूटान ने भारत से कहा कि आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लोगे तो हम आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी देंगे। विदेश नीति, संचार व्यवस्था और सेना सबकुछ आप ही संभालोगे। भारत ने हामी भरी और भूटान की सुरक्षा भारत करता है।

टेस्ला ने मुंबई में खोला अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर

(एजेन्सी)।

टेस्ला आखिरकार मुंबई में अपने पहले शोरूम के उद्घाटन के साथ भारत में आ गई है। शहर के मध्य, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित, 4,000 वर्ग फुट का यह शोरूम इस इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज के भारतीय बाजार में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रवेश का प्रतीक है।

टेस्ला ने भारत में अपने पहले शोरूम, जिसे "एक्सपीरियंस सेंटर" कहा जाता है, के उद्घाटन के साथ औपचारिक रूप से अपना परिचालन शुरू कर दिया है। यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रवेश का प्रतीक है, हालाँकि यह उस विनिर्माण निवेश के बिना हो रहा है जिसकी भारत को लंबे समय से उम्मीद थी।

4,000 वर्ग फुट का यह स्थान एक उत्पादन केंद्र के बजाय एक खुदरा और प्रदर्शन केंद्र के रूप में कार्य करता है। टेस्ला ने देश में तीन अन्य व्यावसायिक संपत्तियाँ भी हासिल की हैं: बेंगलुरु में एक पंजीकृत कार्यालय, पुणे में एक इंजीनियरिंग केंद्र और बीकेसी के पास एक अस्थायी प्रशासनिक कार्यालय।

भारत सरकार द्वारा वर्षों से की जा रही पैरवी और टेस्ला को स्थानीय विनिर्माण के लिए आकर्षित करने हेतु नीतिगत बदलावों के बावजूद, कंपनी ने संकेत दिया है कि फिलहाल उसकी भारत में वाहन बनाने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय, उसने बिक्री शुरू करने के लिए भारत के भारी आयात शुल्क–लगभग 70%–का सामना करते हुए, सीमित संख्या में वाहनों और सहायक उपकरणों का आयात करने का विकल्प चुना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र चाहता है कि टेस्ला, भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करे।

मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि अनुसंधान, विकास और विनिर्माण भारत में ही हो। मुझे यकीन है कि टेस्ला उचित समय पर इस बारे में सोचेगी। उन्होंने कहा, अपनी इस यात्रा में महाराष्ट्र को एक भागीदार मानें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में अपना पहला केंद्र खोलने का टेस्ला का फैसला शहर और राज्य उसके विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा, टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन इस बात का प्रमाण है कि टेस्ला सही शहर और सही राज्य (यानी मुंबई और महाराष्ट्र) में आ गई है। फडणवीस ने कहा कि मुंबई न केवल भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन राजधानी है, बल्कि एक उद्यमशीलता केंद्र भी है।

करोड़ों की मालकिन हैं भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल

(एजेन्सी)।

भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। जिससे उन्होंने पूरी दुनिया में काफी नाम कमाया है। साइना नेहवाल न सिर्फ कोर्ट पर, बल्कि कमाई और लाइफस्टाइल के मामले में भी चैंपियन हैं। वह भारत की पहली महिला शटलर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची। हालांकि, साइना नेहवाल की कुल संपत्ति के बारे में यहां पूरी जानकारी बता रहे हैं। साइना नेहवाल 36 से 40 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश की सबसे अमीर शटलर्स में गिनी जाती हैं। उनकी आमदमी टूनार्मेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट और रॉयल्टी से आती है। लग्जरी घर और गाड़ियां भी उनकी नेटवर्थ का हिस्सा हैं। हरियाणा के हिसार में 17 मार्च 1990 में जन्मीं साइना ने अपने बेहतरीन करियर और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए संपत्ति अर्जित की है। साइना की कमाई का साधन कई स्त्रोतों से आता है। उनकी कुल संपत्ति करीब पांच मिलियन यानी 36 से 40 करोड़ रुपये आंकी गई है। स्पोर्ट्कींड़ा आदि के अनुसार ये लगभग 3 मिलियन डॉलर यानी 22 से 24 करोड़ रुपये के बीच भी हो सकती है। लेकिन अधिकांश नवीनतम रिपोर्ट्स 5 मिलियन डॉलर की ओर इशारा करती हैं।

खेल के प्रति साइना नेहवाल का जुनून, जीवनशैली और कमाई युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा है। साइना नेहवाल ने 2015 में हैदराबाद में 4.6 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर खरीदा था।

अभिनेता और निर्माता धीरज कुमार का हुआ निधन

(एजेन्सी)। वरिष्ठ अभिनेता और टेलीविजन निर्माता धीरज कुमार का निमोनिया से जूझने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिनेता को इस सप्ताह की शुरूआत में गंभीर सांस लेने की समस्या के बाद भर्ती कराया गया था और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की और निजता का अनुरोध करते हुए प्रशंसकों और शुभचिंतकों को उनकी प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती, कुमार हाल ही में नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन समारोह में सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। उन्होंने अपने गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को दशार्ते हुए कहा, "मैं यहाँ विनम्रता के साथ आया हूँ। हालाँकि मुझे वीवीआईपी कहा जाता है, मेरा मानना है कि असली वीवीआईपी भगवान हैं।" कुमार भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत की एक सम्मानित हस्ती थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें हाल ही में नवी मुंबई के खारघर स्थित इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन समारोह में देखा गया था।

कचहरी में फर्जी अधिवक्ता धरपकड़ अभियान, फर्जी अधिवक्ताओं में हड़कंप

कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की जांच करते हुए उड़ाका दल के सदस्य। (छाया: एसबी)

एसबी संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी दीवानी कचहरी से लगायत कलेक्ट्रेट में फर्जी अधिवक्ताओं की भरमार हो गई है। आये दिन दीवानी कचहरी और कलेक्ट्रेट में प्रवेश द्वार पर ही काला कोर्ट, सफेद शर्ट और बैंड लगाये हुए कथित अधिवक्ता दलालों के माध्यम से क्लाइंट पकड़ते हैं और पैसा लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं और तो और मुकदमें में आर्डरशीट पर अधिवक्ता बनकर हस्ताक्षर भी बना देते हैं, फर्जी अधिवक्ताओं के इन फजीवाड़े से रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं की बदनामी होती है।

■ बार द्वय सेन्ट्रल बार और बनारस बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से उड़ाका दल का किया है गठन

ऐसी घटनाओं की शिकायत बार द्वय सेन्ट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन से अधिवक्तागण आये दिन करते रहते हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए बार द्वय द्वारा बाईस सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया।

मंगलवार से फर्जी अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन और सीओपी की जांच दीवानी न्यायालय से लगायत कलेक्ट्रेट में की गई, जांच में दर्जनों फर्जी अधिवक्ता मिले जिनका न तो बार कौंसिल में पंजीकरण था और न ही विधि स्नातक की डिग्री थी, ऐसे व्यक्तियों को पहले दिन कचहरी न आने की चेतावनी देकर छोड़ दिया और दुबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ला इन्टर्नशिप करने वालों को कोर्ट में काला कोर्ट और बैंड न लगाने की चेतावनी दी गई फर्जी अधिवक्ता धड़पकड़ अभियान से फर्जी अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया है।

जांच दल में गौतम कुमार झा, शशांक श्रीवास्तव, राघवेन्द्र दूबे, सत्य प्रकाश सिंह सुनील, अरविंद पाण्डेय, मंगला तिवारी, ओम शंकर श्रीवास्तव, जयश्री पाठक, दीवाकर दूबे, विशाल सेठ, यामिनी शर्मा, अजिताभ सिंह, अश्वनी यादव आशु आदि अधिवक्ता शामिल थे।

बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रथम किश्त वितरण समारोह का आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई जिला के समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रथम किश्त वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह उन लाभार्थियों के लिए था,जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और युवतियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्व-रोजगार प्रदान करने और उनके आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा आज बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों को राशि वितरित की गई।

इस दौरान बिहार लघु उद्यमी योजना के 886 आवेदकों का चयन जिसमें कुल 856 आवेदकों के प्रशिक्षण प्राप्त के उपरांत 606 आवेदकों को प्रथम किस्त की राशि का वितरण समारोह आयोजन समाहरणायल स्थित सभा कक्ष में किया गया। जिसमें चयनित लाभुकों को जमुई के जिला पदाधिकारी श्री नवीन के निदेशानुसार उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल के द्वारा 5 लाभुकों को सांकेतिक चेक का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रु वैसे लोगों को दिए जाते हैं जिसकी मासिक इनकम 6 हजार से कम होती है।

सरकार की सोच है कि जिनकी 6000 से मासिक इनकम कम है वैसे लोगों को ही सहायता कर इनकम को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम में लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक मितेश कुमार शांडिल्य ने कहा कि हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे। मुझे खुशी है कि बिहार के उद्यमी सकारात्मक दृष्टिकोण और भविष्य को लेकर लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं। उनकी सफलता निश्चित है। यहां के लघु उद्यमी विकसित बिहार के ध्वजवाहक हैं और हम उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इन योजनाओं और उद्यमियों की सफलता हमारे लिए उत्साहजनक है। जिले में स्वरोजगार का माहौल दिनों-दिन मजबूत हो रहा है।

बड़ी संख्या में महिलाएं भी आगे आ रही हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाकर उद्योग लगाने के सपने को साकार कर रही हैं। विकसित बिहार में इन योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी। मौके पर सभी संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं सभी लाभुक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किया निरीक्षण

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय। तेघड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, पूर्व एमएलसी सह जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय, आथोर्पेडिक सर्जन डॉ. प्रवीण कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष हीरालाल पोद्दार, तकनीकी प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश राय, उपाध्यक्ष पप्पू कुशवाहा, देव कुमार, मोनू पटेल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह भासो सहित अन्य लोग ने संभावित मुख्यमंत्री नितीश कुमार की यात्रा एवं शिलान्यास स्थल का जायजा लिया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र यात्रा संभावित है। जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पार्टी नेताओं के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सीएम की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी।

'जोश 2025' का आयोजन हर्षोल्लास, ऊर्जा और असाधारण प्रतिभा के साथ किया गया

संजना भारती संवाददाता

टोंक। भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम, प्रताप नगर, में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित वार्षिक इंटरस्कूल खेल महोत्सव 'जोश 2025' का आयोजन हर्षोल्लास, ऊर्जा और असाधारण प्रतिभा के साथ किया गया। यह आयोजन खेल कौशल, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक जीवन्त उत्सव सिद्ध हुआ।

जयपुर के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों की भागीदारी के साथ, जोश 2025 ने ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं, मार्शल आर्ट्स और योगिक प्रदर्शनों की रोमांचक श्रृंखला के माध्यम से खेल भावना को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, रिले रेस, ताइक्वांडो (पूमसे), और रिदमिक योगासना जैसी विविध प्रतियोगिताओं में अद्वितीय फुर्ती और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। शारीरिक उत्कृष्टता के माध्यम से समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव ने युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं की परीक्षा लेने, आपसी सहयोग बढ़ाने और समृद्ध अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया। पूरा वातावरण जोश और उत्साह से गूंज उठा, जब विद्यार्थियों ने अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन प्रस्तुत किए और साथी विद्यार्थियों व शिक्षकों से प्रोत्साहन प्राप्त किया।

विद्यालय की प्राचार्या ने अपने संबोधन में खेलों में अनुशासन और दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी प्रतिभागी विद्यालयों के समर्पण और टीम वर्क की सराहना की।

जोश 2025 न केवल प्रतिभा प्रदर्शन का एक सशक्त मंच बना, बल्कि इसने विद्यार्थियों में खेलों के प्रति गहन रुचि और प्रशंसा की भावना को भी जाग्रत किया, जिससे युवाओं को प्रेरित करने, जोड़ने और उन्हें ऊजार्वान बनाने का अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा किया।

मानव तस्करी विरोधी दिवस पर दी गई जानकारियां

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान द्वारा रेलवे स्टेशन पर प्रभारी रेलवे सुरक्षाबल संदीप कुमार भारती व समस्त स्टाफ एवं जी0 आर0पी0 के समस्त स्टाफ द्वारा मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर अभियान का शुभारंभ किया गया जिसमें प्लेट फॉर्म पर ट्रेन से आने जाने वाले सभी यात्रियों को बाल तस्करी की जानकारी दी गई और प्लेट फॉर्म पर रेडी वाले, चाय की दुकान वाले, पान की दुकान वाले, और टैम्पो, चालक, व यात्रियों को संस्था सचिव, संस्था समन्वयक प्रोजेक्ट मैनेजर, काउंसलर व समस्त स्टाफ ने पम्पलेट देकर विस्तार से बताया और ट्रेनों में भी पम्पलेट स्टीकर चिपकाकर लोगों को जानकारी देकर अभियान चलाया।

तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास मेरी पहली प्राथमिकता: चंद्रप्रकाश सिंह

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा(बेगूसराय)। 143 तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी सह भावी विधायक प्रत्याशी चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसमपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से रूबरू हो रहें हैं। क्षेत्र के लोगों की समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं।

चंद्रप्रकाश सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निजी कोष से कुल 26 जगहों पर सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही संपूर्ण विधानसभा में रोजगार सृजन की अलख जगा रहें हैं। मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि हम जनता की सेवा निःस्वार्थ भाव से करने आएं हैं। आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र को अव्वल बनाना। इनके साथ जनसमपर्क अभियान में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता चल रहे हैं।

सुप्रसिद्ध कवियित्री गीता राठौर गुंजन को मिला काव्य सम्मान

संजना भारती संवाददाता

गत 13 जुलाई को बीसलपुर हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार पातीराम गंगवार के जन्मदिवस पर शिव धाम छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में आयोजित कवि सम्मेलन में गीता राठौर 'गुंजन' का काव्य पाठ बहुत ही शानदार रहा। उनकी मधुर आवाज में काव्य पाठ सुनकर सभी श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर तालियों से उनका स्वागत किया। आपको बता दें नगर पूरनपुर क्षेत्र की उभरती हुई कवयित्री गीता राठौर गुंजन एक संगीत शिक्षिका होने के साथ इस समय एक प्रसिद्ध कवयित्री की भी पहचान बना चुकी हैं।

मुख्य स्नैचर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, छीना हुआ मोबाइल बरामद कर भेजा जेल

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

पंचकूला। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक स्नैचिंग के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 इंचार्ज इंस्पेक्टर दलीप सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 जुलाई को गांव नग्गल, जिला पंचकूला निवासी आरोपी सन्नी उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया।

यह मामला जून माह का है, जब एक महिला ने शिकायत दी थी कि सेक्टर-26 पंचकूला में तीन बाइक सवार युवकों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ दिनों के भीतर आरोपी सुखविंद्र उर्फ बिंद्र और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान उनके कब्जे से वारदात में शामिल मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि दूसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी सन्नी उर्फ गुल्ली तब से फरार था और छिना गया मोबाइल फोन भी उसी के पास था। आरोपी की तलाश में लगातार प्रयास कर रही क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया सूत्रों की मदद से आखिरकार उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से स्नैचिंग में छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।

पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पंचकूला पुलिस की यह कार्रवाई एक बार फिर दर्शाती है कि अपराधियों के लिए कानून से बच पाना आसान नहीं है और अपराध करने के बाद भी उन्हें कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है।

बिहार बदलाव सभा का किया गया आयोजन

एसबी ब्यूरो

मंसूरचक(बेगूसराय)। जनसुराज द्वारा मंसूरचक प्रखंड क्षेत्र के नारायण पुर चौक के समीप बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बछवाड़ा विधानसभा सह प्रभारी गोपाल पोद्दार और मंच संचालन भावी विधायक प्रत्याशी बछवाड़ा विधानसभा अशोक कुमार चौधरी ने किया।

उक्त मौके पर मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष जनसुराज डॉ. रजनीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन की हुंकार जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया है। इसकी गूंज अब घर घर में होने लगी है। वहीं अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में इसबार वोट अपने बच्चों के नाम पर करें। गोपाल पोद्दार ने भी कार्यक्रम के दौरान जनसुराज की उपलब्धि पर परिचर्चा किया।

मौके पर प्रमंडलीय अभियान समिति के अध्यक्ष रवि रौशन, बछवाड़ा विधानसभा प्रभारी अशोक सिंह, सोलंकी, बछवाड़ा विधानसभा सह प्रभारी उमेश चौधरी, रामविलास निर्मोही, गणपति सदा, उमेश राम, अकलू सदा, बोढ़न तांती, महेंद्र महतो, सोनी कुमारी, काजल कुमारी, उषा रानी, ममता देवी, राम अधिक महतो, सुरेंद्र सदा, वकील दास, सहित अन्य लोग मौजूद थे।

खानपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने फरार चल रहे दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को भेजा जेल

संजना भारती संवाददाता

अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर/खानपुर। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बीती रात विशेष छापामारी अभियान के तहत पुलिस फोर्स के साथ गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के चकोटी गाँव में छापामारी कर समस्तीपुर न्यायालय से निर्गत-NBW वारंट में फरार चल रहे अभियुक्त (1) पल्लू राय (2) श्रवण राय दोनों पिता राजेन्द्र राय-ग्राम-चकोटी-थाना खानपुर जिला समस्तीपुर को छापामारी के क्रम में घर से ही गिरफ्तार कर थाना लाया गया।

वही गिरफ्तार दोनों अभियुक्त के बारे में पूछने पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पल्लू राय व श्रवण राय पिता राजेन्द्र राय ग्राम-चकोटी-थाना खानपुर के विरूद्ध समस्तीपुर न्यायालय से निर्गत NBW वारंट में फरार चल रहा था। जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस फोर्स के सहयोग से बीती घर से ही गिरफ्तार कर थाना लाया गया। तथा गिरफ्तारी कागजात तैयार कर थाना के पुलिस पदाधिकारी व चौकीदार के साथ उचित अभिरक्षा में सरकारी वाहन से माननीय न्यायालय समस्तीपुर में उपस्थापन हेतु भेजा गया है।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, '**संजना भारती**' को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संपर्क करें: दैनिक संजना भारती, समाचार पत्र नई दिल्ली

वाटसेप नम्बर: 9871221635

सीईटी 2025: जिला में 53 परीक्षा केंद्रों पर होगी करीब 70 हजार परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था: डीसी

26-27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी: डीसी

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 26-27 जुलाई को ग्रुप-सी की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर जिला प्रशासन, द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। डीसी उत्तम सिंह ने यह जानकारी वीसी में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सीईटी की परीक्षा को जिला में नकल रहित करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों व करनाल जिला के परीक्षार्थी जो दूसरे जिला में परीक्षा देने के लिए जाएंगे जिला प्रशासन द्वारा उनके लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा कानून व सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। उपायुक्त उत्तम सिंह ने निर्देश दिए कि सामान्य पात्रता परीक्षा जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए जिला में 40 शिक्षण संस्थाओं में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। इन केंद्रों पर चारों शिफ्टों में करीब 70 हजार परीक्षार्थियों के बैठने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 व 27 जुलाई को दो-दो कुल सत्रों में परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में आयोग की एसओपी की पालना की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्राप्त डाटा के अनुसार एक शिफ्ट में करीब 17 हजार 472 बच्चे परीक्षा देगें। उक्त दोनों दिनों की कुल चारों शिफ्टों को मिलाकर जिला में करीब 70 हजार बच्चें परीक्षा देगें। डीसी ने कहा कि उपमंडल अधिकारी (ना.) परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की एक बार पुनः निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं का जायजा ले। इस कार्य में शिक्षा विभाग व अन्य अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने जिला से बाहर परीक्षा देने तथा बाहर से जिला में आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था की एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है।

इस अवसर पर एसपी गंगाराम पुनिया, एसडीएम अनुभव मेहता, सीटीएम मोनिका शर्मा, आरटीए विजय देशवाल, जीएम रोडवेज कुलदीप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सुदेश कुमारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी आमजन एवं कांवड़िए यातायात नियमों का करें पालन: डीसी प्रीति

डीसी कैथल प्रीति।

संजना भारती संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि के दिन हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लाकर पास के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए पुलिस अपने पुख्ता इंतजाम रखे। इसके साथ ही सभी आमजन एवं सभी कांवड़ यात्री यातायात नियमों का पालन करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी अपील की है कि वे मुख्य सड़कों से थोड़ा पीछे हट कर शिविर लगाएं। उन्होंने कांवड़ियों से भी अपील की है कि वे तेज आवाज में संगीत न बजाएं।

वाहनों की छतो पर बैठ कर यात्रा न करें, क्योंकि ऐसा करने से हादसा होने की संभावना रहती है। कांवड़ यात्री स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस चौकी या 112 हेल्पलाइन पर दें। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए योजना तैयार करें।

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला दौर था आपातकाल: ज्योति सैनी

आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लगाई गई प्रदर्शनी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला दौर था। इस दौरान लोगों को यातनाएं दी गई। आंदोलनकारियों को जेलों में डाल दिया गया था। 25 जून 1975 की रात में देश में आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की हत्या की गई थी। यह देशवासियों के लिए काफी दुखदायी था। विभिन्न आयोजनों एवं प्रदर्शन के माध्यम से आपातकाल से अनभिज्ञ युवा पीढ़ी को हकीकत से रूबरू करवाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की मजबूती के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।

ज्योति सैनी मंगलवार को लघु सचिवालय में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर लगाई गई प्रदर्शनी के उद्घाटन एवं अवलोकन उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहीं थीं। इसके साथ ही एक प्रदर्शनी डा. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में लगाई गई है। प्रदर्शनी अवलोकन उपरांत उन्होंने कहा कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाता है कि जब भारत के संविधान में शामिल नागरिकों के अधिकारों को रौंदा गया था, तो क्या हुआ था। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी समय है, जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ा झेली थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए रातों-रात आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया दिया गया था। नागरिक अधिकारों को निर्लंबित कर दिया गया था। 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो नरेंद्र मोदी ने लाखों देशवासियों की भांति तत्कालीन सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोकतंत्र की इसी चेतना और सतर्कता को जीवित रखने के लिए भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया है। भाजपा जिला महामंत्री सुरेश संधू ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का परिणाम था। यह इतिहास में काल अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भाजपा महामंत्री मनीष शर्मा ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या का एक सबूत है।

यह प्रदर्शनी आमजन को यह बताती है कि उस समय सत्ता के लालच में तत्कालीन सरकार ने आम जनों पर अत्याचार किया था। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आपातकाल के दौरान के हालातों को जाना।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को

आपसी समझौते से सुलझेंगे मुकदमे -डॉ. इरम हसन

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगामी 13 सितंबर 2025 को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने बताया कि यह लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार आयोजित की जा रही है।

डॉ. इरम हसन ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को तेजी से, सुलभ और निःशुल्क न्याय प्रदान करना है। इस दिन अदालतों में लंबित कई प्रकार के मुकदमों जैसे कि देनदारी, पारिवारिक विवाद, सिविल व आपराधिक शमनीय मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, बिजली-पानी बिल से संबंधित केस, चेक बाउंस व बैंक रिकवरी केस आदि को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले अदालतों में लंबित हैं, वे लोक अदालत में अपने वकील की मदद से अथवा सीधे आवेदन देकर अपने मुकदमे का निपटारा आपसी सहमति से कर सकते हैं। इससे उन्हें न केवल लंबी अदालती प्रक्रिया से राहत मिलेगी, बल्कि वे समय और धन दोनों की बचत कर सकेंगे।

डॉ. हसन ने संबंधित पक्षों से अनुरोध किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने मामलों का समाधान करवाएं और विवाद मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किए गए फैसले अंतिम होंगे और उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। जो व्यक्ति या पक्ष अपने मामले को लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या अपनी संबंधित अदालत में आवेदन दे सकते हैं।

धान की कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य: वजीर सिंह

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि राज्य में धान की पराली जलाने की समस्या तथा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा राज्य (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए है। जारी निदेर्शों के अनुसार हरियाणा राज्य में धान की कटाई करने के इच्छुक कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिक कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाएंगे तथा राज्य में किसी भी कम्बाइन हार्वेस्टर को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के बिना धान की कटाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कटाई के बाद खुले खेत में धान की पराली जलाना राज्य और उससे सटे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है और इस तरह की हरकतें मिट्टी और पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है।

उन्होंने बताया कि धान की कटाई प्रक्रिया के दौरान जब कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ा जाता है, तो धान के अवशेषों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, जिससे किसानों को धान के अवशेषों को जलाए बिना अपनी अगली फसल बोने में सुविधा होती है। जिससे किसान आगजनी नहीं करता है और वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए धान की कटाई करने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिकों को कम्बाईन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना अनिवार्य किया जाऐगा। उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मालिको से आग्रह किया है कि वे सभी अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवा लें ताकि उनको सीजन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि वे फसल कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेषों में आग न लगाएं बल्कि इसको पशु चारे के तौर पर या खेत में ही मिलाकर उपयोग करें।

डॉ वजीर सिंह ने बताया कि अकसर किसान धान फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि की उर्वरता में कमी आती है व जान माल की हानि का डर भी बना रहता है। सरकार द्वारा फसल अवशेषों में आगजनी करने पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला में पिछले दो वर्षो से आगजनी की घटनाओं में लगभग 60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के प्रयास व जिला के प्रगतिशील किसानों के सहयोग से हरसेक से प्राप्त होने वाली लोकेशन जो कि खरीफ 2021 में 957 दर्ज की गई थी, खरीफ 2022 में घटकर 301 दर्ज की गई थी, खरीफ 2023 में केवल 126 व खरीफ 2023 में केवल 95 एएफएल दर्ज की गई है। खरीफ 2023 में रेड जोन गांवों की संख्या 10 व येलो जोन गांवों की संख्या 53 थी जो घटकर खरीफ 2024 में रेड जोन गांवों की संख्या 2 व येलो जोन गांवों की संख्या 24 रह गई है। इन गांवों में जागरूकता के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सभी गांवों में किसानों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते हैं, इसके अलावा प्रत्येक गांव में मुनादी व धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जाता है। स्कूल/कॉलेज में पढ़ने में वाले बच्चों के सहयोग से रैलियां व प्रभात फेरी निकाली जाती है। गांव व खंड अनुसार सभी किसानों के वाट्सएप ग्रुप बनाये गये हैं व पिछले सालों में जिन किसानों द्वारा खेतों में आगजनी की गई थी, उन सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस वर्ष आगजनी न करें।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस वर्ष फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं में जीरो बर्निंग का लक्ष्य दिया गया है । इन आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए गांव स्तरीय कमेटी/एनफोर्समेंट टीम का गठन किया जाता है जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, सम्बन्धित पटवारी व ग्राम सचिव सदस्य हैं। साथ ही पशुपालन विभाग व बिजली विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी इस कार्य के लिए लगाए जाते हैं।

राजौंद में ब्रह्माकुमारी बहनों का 'एक पेड़-मां के नाम' अभियान लगातार जारी

ब्रह्माकुमारी आश्रम राजौंद, क्षेत्र को हरा भरा बनाने की ओर अग्रसर

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजौंद द्वारा चल रहे 'एक पेड़-मां के नाम' अभियान में मंगलवार को ब्रह्माकुमारी बहनों द्धारा पौधे लगाए गए। राजौंद क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए खंड राजौंद के अलग-अलग गांव, गलियों, वार्ड में जाकर बहनें वृक्षारोपण के साथ-साथ नागरिकों को पेड़-पौधों की देखभाल के लिए जागरूक कर रही है। मंगलवार को नगर के असंध रोड पर स्थित फार्म हाउस कंवर सिंह में पौधरोपण किया गया।

ब्रह्माकुमारी बहन आशा ने बताया कि प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ निःशुल्क दिया, लेकिन आज मानव के स्वार्थवादी दृष्टिकोण तथा उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति और औद्योगिकीकरण के कारण उसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है जो अभी उसे संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमें ना तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, ना अन्य दूसरे स्वस्थ संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। बीके नीलम व बीके सरिता ने भेजे अपने संदेश में कहा कि वास्तव में यह बाहरी प्रदूषण मानव मन के आंतरिक प्रदूषण का ही परिणाम है। आज खेतों में जो अन्न उपजा रहे हैं उसमें भी कीटों को मारने के लिए जो जहरीली कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही है उससे अनाज भी विषैला और प्रदूषित हो रहा है। अतः प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए मन को शुद्ध बनाएं, प्रकृति के प्रति उदारता का भाव रखें।

ब्रह्माकुमार भ्राता राजयोगी मेहर चंद ने भेजे अपने संदेश में कहा है कि ब्रह्माकुमारी संस्थान में हम राजयोग मेडिटेशन द्वारा पवित्र, शांति के प्रकंपन चारों ओर फैलाकर प्रकृति के पांचों तत्वों को सतोप्रधान बनाने का प्रयास करते हैं और हम सब के सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से भारत फिर से प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न, विश्व गुरु, सिरमौर बन जाएगा। बीके ऊषा दीदी ने बच्चे, बड़े सबका आवाह्न करते हुए कहा कि चलिए एक पेड़, हर एक लगाए, इस धरा को स्वर्ग बनाए।

दीदी ने प्रकृति को शांति, शक्ति के वाइब्रेशंस देने के लिए गहन योग की अनुभूति का संदेश दिया है। ब्रह्माकुमारी बहनों ने नागरिकों से अनुरोध किया कि एक पेड़ धरती माता के नाम लगाकर, उस पेड़ की देखभाल करें। उसे बड़ा होने दें, नष्ट होने से बचाए। यह पेड़ हमें शुद्ध वायु, छाया, औषधि, फल, फूल से निरंतर, बिना भेदभाव, अनन्त काल तक हमारी व आने वाली मानव जाति की सेवा करते रहेंगे।

अधिकारी आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें: रणबीर गंगवा

एसबी संवाददाता/चंडीगढ़। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टोरलेंस की नीति पर काम कर रही है, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। श्री गंगवा मंगलवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से रुबरू हुए थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जनता को क्वालिटी के साथ मूलभुत सुविधायें मिलें। रोहतक में जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े जिन 42 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, वहां सिविल कार्यों को करवाने में अनियमितताएं बरती गयी थीं। दोनों विभागों पर उनकी नजर है, अधिकारी आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर तय समय पर हल करें, इस बारे भी निर्देश दिए जा चुके हैं। हरियाणा में बारिश के पानी की निकासी के व्यवस्था के बारे में पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्ति पंप सैट भी लगाए गए हैं। साथ ही विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि इस संबंध में आमजन की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पीडब्लयूडी विभाग के अंतर्गत 30664 किलोमीटर की सड़कें आती हैं।

गांव करोड़ा में सीएमओ कैथल डॉ रेनू चावला के निर्देशन में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कार्यक्रम के अध्यक्ष रहें एसएमओ राजौंद डॉ कीर्ति कुमार शर्मा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। सीएचसी राजौंद के अंतर्गत आने वाले गांव करोड़ा में सीएमओ कैथल डॉ रेनू चावला के निर्देशन में व एसएमओ राजौंद डॉ कीर्ति कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' विषय पर बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश व समाज का भविष्य बेटीयों की परवरिश पर निर्भर करता है। समाज में बेटी को दया, पीड़ा, तथा अन्याय सहन करने पड़ते हैं। कुछ गाँव में बेटीयों की जन्म-दर, बेटों से कम है। कुछ गाँव में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम पैदा हो रही है। यह एक गंभीर समस्या है। यदि बेटी नहीं होगी तो समाज का तानाबाना ही बिगड़ जाएगा।

एसएमएस ने कहा कि बेटा और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। बेटियां भी मां-बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती है। बेटियां आज देश के हर फील्ड में जाकर देश व समाज की सेवा कर रही है। बेटियों की संख्या घटने से समाज में भय, असंतोष, अपराध बढ़ता है जिससे समाज का ताना-बाना बिगड़ जाता है।

समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बेटों व बेटियों की संख्या समान रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन निरंतर जागरूकता अभियान चला कर, बैठकों का आयोजन कर, गांव व नगर में जागरूकता रैलियां, गोष्ठियां आयोजित कर नागरिकों को समझ रहे हैं कि बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाना अपराधहै। यदि लड़कियां, लड़कों की अपेक्षा कम पैदा होंगी तो यह समाज और देश के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे।

आज की सभा में भाग लेने वालों में शामिल है एमपीएचएस मेल राजेश कुमार, एमपीएचएस फीमेल सरोज, काजल, रेखा, सरस्वती, कवीता, नीशा, कोमल, खुशबू, पूनम, सुमन, मोनिका, प्रियंका, सिमरन, मेनका, मुन्नी, सविता, मंजू, सहित अन्य की उपस्थिति रही।

आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लघु सचिवालय में लगाई गई जागरूकता प्रदर्शनी

महापौर रेनू बाला गुप्ता ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में संविधान हत्या विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई। महापौर रेनू बाला गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सचिवालय में पहुंचे लोगों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी एक माह तक लगी रहेगी। प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल के दौरान दी गई यातनाओं व उस दौरान लोकतंत्र प्रहरियों की भूमिका प्रदर्शित की जा रही है।

इस मौके पर महापौर रेनू बाला गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज लगाई गई यह प्रदर्शनी 25 जून 1975 के उस काले अध्याय के बारे में याद दिलाती है, जब राजनीतिक कारणों से देश में आपातकाल थोपा गया था। इस दौरान लोगों को यातनाएं दी गईं, उनकी जबरन नसबंदी की गई और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश के नायकों जैसे जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिन्होंने लोगों को आगे बढने के लिए प्रेरित किया।

महापौर ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल के दौरान के 21 महीनों की विस्तृत जानकारी साझा की जा रही है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे इन नेताओं के अथक प्रयासों से देश आपातकाल की बेडियों से बाहर निकल पाया। प्रदर्शनी का लक्ष्य युवाओं को देश के इन जननायकों और उनके योगदान के बारे में जागरूक करना है।

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित में लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान देने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को सामने लाकर उनका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में हर वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है। हम संकल्प से सिद्धि के 11 वर्ष मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसी संकल्प को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र अथवा वर्ग विकास से अछूता न रहे।

महापौर रेनू बाला गुप्ता ने स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल को तीसरा स्थान प्राप्त करने पर शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता किसी पुरस्कार के पाने के लिए किए जा रहे प्रयास नहीं होते, अपितु यह एक सतत प्रक्रिया है।

उन्होंने कहा कि यह सामूहिक सहयोग से सम्भव हुआ है। 17 जुलाई को मिलने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार के क्षण हम सबका गौरव बढ़ाएंगे।

हरियाणा में पेड़ कटाई की एनओसी प्रक्रिया होगी सरल

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पेड़ काटने हेतु एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दिए गए आवेदन पर यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे एक बार में ही दर्ज किया जाए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को बार-बार परेशान न होना पड़े। श्री राव नरबीर सिंह आज हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड के डीएफओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।